

POLICE DEPARTMENT, KERALA

No. Q2/107862/2020/PHQ


Police Headquarters,
Thiruvananthapuram
Email: phq.pol@kerala.gov.in
Ph: 04712721547
Dated: 24/09/2020

Circular No. 38 /2020/PHQ

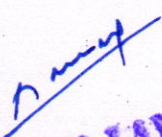
Sub: The Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 - Compliance -
instruction reg:-

Ref: Central Government Notification NO. G.S.R 165 (E) dated 9/3/2020 Published in
the Gazette of India Extra Ordinary Part II - Section 3 Sub Section (i) dated
9/3/2020.

The Copy of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 which
repealed the POCSO Rules, 2012 is here by circulated for the information of all officers
concerned. All officers are directed to strictly comply with the provisions in the new
POCSO Rules. Whenever cases under POCSO are reported, an express report shall be
sent to PHQ on the date of report itself. Q2 will collect such details, collate and store
such data according to the gender. Q2 will compare these data with the Criminal
Intelligence Bureau (CIB) of SCRB after every monthly Crime Review meeting. After
that the Q2 will furnish a copy of the statement to the designated Nodal Officer
immediately


24/09/2020
for DGP & State Police Chief
Kerala, Thiruvananthapuram

- To:
1. All Officers in List A, B and C (as per Circular 28/2020) for information.
 2. All DPCs and all SHOs of all Police Stations.
 3. CAs to all Officers in PHQ
 4. Police website/Circular book/D Space.


AIG (PG & LA)
PHQ



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032020-218601
CG-DL-E-11032020-218601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]
No. 141]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2020/फाल्गुन 19, 1941
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2020/PHALGUNA 19, 1941

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

सा.का.नि. 165(ब)—केंद्रीय सरकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 45 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है।

(ख) "जिला बालक संरक्षण एकांक" (डीसीपीयू) से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बालक संरक्षण एकांक अभिप्रेत है।

(ग) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, बाल विकास या अन्य सुमंगल विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसकी संप्रेषण क्षमता अभिघात, निःशक्तता या किसी अन्य भेद्यता से प्रभावित ऐसे बालकों के साथ संप्रेषण को सुचारु बनाने की आवश्यकता है।

(घ) "विशेष शिक्षक" से सीखने और संवाद की चुनौतियों, भावनात्मक और व्यावहारिक मुद्दों, आरंभिक निःशक्तताओं और विकासपरक मुद्दों सहित तरीकों से बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं और आवश्यकताओं का समाधान करके निःशक्त बालकों में संप्रेषण करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए निःशक्तता पद का वही अर्थ होगा जैसा दिव्यांगजन अधिकांश अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड(घ) में परिभाषित किया गया है।

(1)